श्री जी. सी. मितल और जी.एस. चहल न्यायमूर्ति के समक्ष

शशि कांत वोहरा और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 757

4 सितंबर. 1990

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973—एस. 13—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—एस. 115—अधिसूचना दिनांक 2 जून, 1979 और छूट अधिसूचना दिनांक 30 दिसंबर, 1987-ग्रामीण छोटी औद्योगिक इकाइयों को छूट दी गई 1979 अधिसूचना द्वारा कर का भुगतान - दो की अवधि के लिए छूट दी गई

वर्ष-उद्योग विभाग द्वारा जारी छूट प्रमाण पत्र शर्त बनी रियायत का लाभ उठाने के लिए मिसाल-1987 की अधिसूचना में आगे की शर्त रखी गई है-ऐसी इकाइयों का टर्नओवर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए - की वैधता 1987 अधिसूचना- टर्नओवर वाली छोटी इकाइयों से रियायत वापस लेना 5 लाख रुपये से अधिक—प्रॉमिसरी एस्टॉपल के नियमों का उल्लंघन है—छूट नहीं दी जा सकती वापस लिया जाए - धारा 13 के तहत जारी अधिसूचना अधीनस्थ कानून है न कि ए विधायी' अधिनियम.

माना गया कि हरियाणा जनरल सेल्स के तहत कर में छूट की अनुमति दी गई है कर अधिनियम. लघु उद्योगों के लिए 1973, अधिसूचना दिनांक 2 जून 1979 द्वारा 30 तारीख की आक्षेपित अधिसूचना के माध्यम से वापस नहीं लिया जा सका दिसंबर, 1987 और हरियाणा सरकार को पीछे हटने से रोक दिया गया वचन-बंधन के नियम द्वारा छोटी औद्योगिक इकाइयों को रियायत।

(पैरा 16)

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम। 1973—एस. 13—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—एस. 115—अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त. 1973 और 30 दिसंबर, 1987—1973 की अधिसूचना द्वारा खादी और ग्रामोद्योग को छूट दी गई 1979 की अधिसूचना द्वारा वापस ले लिया गया - केवल रियायत होने के कारण, इसे वापस लिया जा सकता था किसी भी समय - वचनबंधन का नियम लागू नहीं होता है। माना गया कि खादी और ग्रामोद्योग के मामले में, का नियम वचनबद्ध। विबंधन आकर्षित नहीं है. यह उन्हें और इसे दी गई रियायत थी राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय वापस

लिया जा सकता है। द. कि रद्द खादी उद्योग से संबंधित अधिसूचना दिनांक 30 दिसंबर, 1987 कानूनी है और हरियाणा के राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत। (पैरा 17)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि कृपया इस मामले से संबंधित रिकार्ड तलब करें और उसका अवलोकन करें

माननीय न्यायालय इस पर प्रसन्न हो सकता है:-

(ए) परमादेश घोषणा की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना अधिसूचना अनुलग्नक पी-1, विशेष रूप से प्रतिबंधित करने वाला खंड सालाना टर्नओवर 5 लाख की सीमा तक ही छूट का लाभ

असंवैधानिक और शून्य.

(बी) निषेध की प्रकृति में एक रिट या निर्देश जारी करें मूल्यांकन प्राधिकारी को लेवी, अधिरोपण, मूल्यांकन से रोकना और बिक्री/खरीद कर की वसूली।

(सी) कोई अन्य उचित रिट, निर्देश का आदेश जारी करें जैसा समझा जा सकता है मामले की परिस्थितियों में फिट।

(डी) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता से मुक्ति।

(ई) प्रस्ताव की अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता से उत्तरदाताओं को मुक्ति

(एफ) इस रिट याचिका की लागत का पुरस्कार दें।

आगे प्रार्थना की गई है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई की जाए कृपया अधिसूचना (अनुलग्नक पी-1) पर रोक लगाई जाए और कर की वसूली की जाए न्याय हित में याचिकाकर्ताओं से रोक लगाई गई।

याचिकाकर्ताओं के वकील गोविंद गोयल।

एस. सी. मोहंता, ए.जी. हरियाणा के साथ एस. के. सूद, डी.ए. हरियाणा

निर्णय

माननीय जी. एस. चहल न्यायमूर्ति

1. चूंकि कानून का सामान्य प्रश्न यहां शामिल है, इसलिए निर्णय वर्तमान रिट याचिका और सिविल रिट याचिका संख्या 1026, 1120, 1123, 1244, 1338, 1396, 1553, 2204, 2292, 2794 का

निपटान करेगा। 2795, 3449, 3480, 3573, 3574, 3580, 3631, 3644, 3681, 3756, 3921, 3924, 3925, 4146, 4213, 4375, 4753, 4987, 5216, 5285, 551 3, 6802, 7265, 7524, 10125 और राज्य हरियाणा हरियाणा द्वारा जारी वास्तविकता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधीन, अधिनियम के तहत कर के भुगतान से छूट दी गई थी, और छूट थी दो वर्ष की अवधि के लिए. ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए इस लाभ के अनुदान का सरकारी मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था। करों में छूट के रूप में प्रोत्साहन देने की उक्त नीति से प्रभावित होकर, याचिकाकर्ताओं ने कपास के बीज के निर्माण और डिलिन्टिंग के लिए जिला रोहतक के गाँव चंडी और मदीना में ग्रामीण छोटी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कीं। याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर उनके पक्ष में अधिसूचना की शर्तों के अनुरूप छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने उन तारीखों का निम्नलिखित विवरण दिया जिस पर उन्हें छूट प्रमाण पत्र प्रदान किए गए थे:

2. एस. याचिकाकर्ता का नाम दिनांक छूट संख्या प्रमाणपत्र प्रदान किया गया ----------

1. अमर जनरल मिल्स, चंडी 11-11-1987

2. अंकुर कॉटन स्टीड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, मौजा कुंताना 25- 9-1987

3. डायमंड डेलिन्टर इंडस्ट्रीज, मदीना 3-4-1987

छूट का प्रमाणपत्र प्रारंभ में एक अवधि के लिए था वर्ष, लेकिन छूट अधिसूचना अनुलग्नक पी2 के अनुरूप एक और वर्ष के लिए विस्तार योग्य था।

3. हरियाणा 2 जून को अधिसूचना जारी की गई, 1979, अनुलग्नक पी2, जिसके तहत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद स्थापित सभी ग्रामीण लघु औद्योगिक इकाइयाँ, जिनकी मशीनरी और उपकरणों पर पूंजी निवेश रुपये से अधिक नहीं था। 1,00,000 को उद्योग विभाग, **सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित),हरियाणा**हरियाणा**धारा 13 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए** के राज्यपाल हरियाणा. छोटे उद्योगों के संबंध में, हम 1988 की रिट याचिका संख्या 757 में निहित तथ्यों का उल्लेख करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने 30 दिसंबर, 1987 की अधिसूचना, अनुबंध पी 1 की वैधता को चुनौती दी है। उल्लिखित तथ्यों के अनुसार ने 30 दिसंबर, 1987 को एक नई अधिसूचना, अनुलग्नक पी1 जारी की, जिसमें 2 जून, 1979 की छूट अधिसूचना, अनुलग्नक पी2 सहित पिछली सभी अधिसूचनाओं को हटा दिया गया, और इस प्रकार यह प्रावधान किया गया कि अनुलग्नक पी2 द्वारा कवर की गई प्रकार की इकाइयाँ, के टर्नओवर तक ही छूट के हकदार हैं। 5,00,000 और पहले से दी गई छूट को नई अधिसूचना के अनुसार संशोधित माना जाएगा। आक्षेपित अधिसूचना में निम्नलिखित खंड ने याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है:

(3) ऐसी इकाइयाँ एक वर्ष में पाँच लाख रुपये से अधिक के टर्नओवर पर छूट की हकदार होंगी।

(2.) उन इकाइयों के मामले में जिनके पक्ष में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा छूट प्रमाणपत्र पहले ही दिए जा चुके हैं, ऐसे छूट प्रमाणपत्रों को इस अधिसूचना की शर्तों के अनुसार संशोधित माना जाएगा जैसे कि ऐसे प्रमाणपत्र इस अधिसूचना के तहत जारी किए गए थे। " का कारोबार हुआ। याचिकाकर्ताओं को 5 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं' इकाइयाँ हर महीने, लेकिन चूँकि स्थापित इकाइयाँ हर दिन 6 टन कपास के बीज का उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं, इसलिए इकाइयों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना भी आवश्यक है, जैसा कि बैंकों और विभिन्न संस्थानों द्वारा निर्धारित किया गया है। हरियाणा के भीतर कार्यरत इसकी विकेन्द्रीकृत इकाइयों को छोड़कर, सहकारी समितियों और व्यक्तियों के सभी वर्ग राज्य के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट होकर कि कुटीर उद्योगों के हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, 1 जनवरी से छूट देते हैं 1988, - (ए) खादी आश्रम, पानीपत और हरियाणा याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि वे खादी और ग्रामोद्योग थे और उन्हें इसके प्रचार के लिए फैक्स के भुगतान से छूट दी गई थी। इस छूट का दावा 10 अगस्त, 1973 की अधिसूचना, अनुबंध पी2 के तहत किया गया था और कर छूट की अनुमति दी गई थी। 30 दिसंबर, 1987 की आक्षेपित अधिसूचना के तहत, पिछली अधिसूचना को हटा दिया गया था और इसे निम्नानुसार प्रदान किया गया था: ". . . . . .

4. **1988 के W. P. 3644**राज्य वित्तीय निगम। लागू अधिसूचना, लागू होने पर, याचिकाकर्ताओं को वर्ष में केवल एक महीने के लिए छूट देगी। प्रतिवादी-अधिकारियों ने लिखित बयान दाखिल करके रिट याचिकाओं का विरोध किया। तथ्यों पर विवाद नहीं किया गया था, लेकिन यह दलील दी गई थी कि किसी क़ानून के ख़िलाफ़ रोक का कोई नियम नहीं हो सकता है और हरियाणा, सहकारी समितियां और ईंट-भट्ठे या हाइड्रोलिक सल्फर चीनी संयंत्र चलाने वाले व्यक्ति, जब तक कि उनका कारोबार एक वर्ष में पांच लाख रुपये से अधिक न हो; (बी) ईंट-भट्ठे या हाइड्रोलिक सल्फर चीनी संयंत्र चलाने वाली सहकारी समितियां और व्यक्ति, जब तक उनका कारोबार एक वर्ष में पचहत्तर हजार रुपये से कम रहता है; और (सी) खादी आश्रम, पानीपत, और राज्य हरियाणा, जिनके मामले में एक वर्ष में टर्नओवर की कोई अधिकतम सीमा नहीं है; इन याचिकाओं का भी उत्तरदाताओं ने छोटे उद्योगों की तरह ही समान आधार पर विरोध किया है।

5. 30 दिसंबर, 1987 की अधिसूचना, अनुलग्नक पी1 की वैधता, जो 1 जनवरी, 1988 से प्रभावी हुई, पर एकल न्यायाधीश द्वारा सतगुर ऑयल मिल्स v. राज्य हरियाणा [**1989 ] 73 STC 341 (पी और एच**); **ILR (1989) 1 P और H 175**, और रिट याचिका की अनुमति देते हुए, यह माना गया कि 30 दिसंबर, 1987 की अधिसूचना लागू नहीं होती याचिकाकर्ताओं की औद्योगिक इकाइयों

को और वे मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा उनके पक्ष में जारी छूट प्रमाण पत्र के आधार पर कर के भुगतान से दो साल की छूट के हकदार होंगे।

6. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों के मद्देनजर, भारत जनरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड v। राज्य महाराष्ट्र [1989] 72 एसटीसी 354; **(1988) III एसवीएलआर (टी) 120**; जेटी (1988) 4 एससी 204, रिट याचिकाओं को एक बड़ी बेंच को भेजा गया था और इस तरह, ये रिट याचिकाएं हमारे सामने आई हैं। छूट अधिसूचना दिनांक 2 जून, 1979, अनुलग्नक पी 2 में, हरियाणा के राज्यपाल ने छूट देते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्देशित किया था: " . . . . . इस बात से संतुष्ट होने पर कि ग्रामीण उद्योगों के हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद स्थापित सभी ग्रामीण लघु औद्योगिक इकाइयों को आधिकारिक राजपत्र में छूट देता है, जिनका पूंजी निवेश मशीनरी पर होता है और उपकरण की कीमत एक लाख रुपये से अधिक नहीं है और जिसके पक्ष में हरियाणा राज्य**हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत कर के भुगतान से** किसी भी सामान की खरीद या बिक्री पर। . . . . . " यह छूट दो शर्तों के अधीन थी: " 1. इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र में एक छूट प्रमाण पत्र उनके द्वारा संबंधित जिले के मूल्यांकन प्राधिकारी से इस संबंध में ऐसे प्राधिकारी को किए गए आवेदन पर प्राप्त किया जाता है; 2. छूट छूट प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए होगी। " अधिसूचना दिनांक 30 दिसंबर, 1987, अनुलग्नक पी 1 के माध्यम से, हरियाणा के राज्यपाल ने निम्नलिखित शर्तों में अधिसूचना जारी की: ". . . . . इस बात से संतुष्ट होने पर कि ग्रामीण उद्योगों के हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा 22 जून, 1979 को या उसके बाद स्थापित सभी ग्रामीण लघु औद्योगिक इकाइयों, जिनकी पूंजी मशीनरी और उपकरण पर निवेश एक लाख रुपये से अधिक नहीं है और जिसके पक्ष में हरियाणा राज्य के उद्योग विभाग द्वारा वास्तविकता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। , **हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973,** के तहत कर के भुगतान से। . . . . . " रियायत का लाभ उठाने के लिए आगे की शर्तें छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करना थीं; छूट दो साल के लिए थी और छूट रुपये से अधिक के टर्नओवर पर नहीं थी। एक साल में 5,00,000. इस अधिसूचना की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि याचिकाकर्ताओं ने अनुबंध पी 2 में किए गए वादे पर काम किया है, राज्य सरकार नियम से बंधी हुई है प्रॉमिसरी एस्टोपेल और छूट की अवधि को कम नहीं किया जा सकता था, न ही कुल टर्नओवर पर प्रतिबंध तय किया जा सकता था। विवादित अधिसूचना का पूर्वव्यापी प्रभाव भी है और यह वस्तुतः सभी रियायतें वापस लेने जैसा है। प्रतिवादी-राज्य ने तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के मामले को चुनौती नहीं दी है, लेकिन यह दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने कानून की अपनी संप्रभु शक्तियों का

प्रयोग किया है और वह छूट अधिसूचना, अनुबंध पी2 में दी गई रियायतों को वापस ले सकती है। इसके अलावा अधिसूचना का स्वरूप संभावित था और इससे कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ।

8. मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स सी. लिमिटेड vराज्य उत्तर प्रदेश [1979(एससी); AIR 1979 SC 621 और जहां तक ये इस मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं, हम (एआईआर के) हेडनोट से निम्नलिखित उद्धरण उद्धृत करते हैं: ". . . . . वचनबंधन का सच्चा सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि जहां एक पक्ष ने अपने शब्दों या आचरण से दूसरे से एक स्पष्ट और स्पष्ट वादा किया है जिसका उद्देश्य कानूनी संबंध बनाना या भविष्य में उत्पन्न होने वाले कानूनी संबंध को प्रभावित करना है, यह जानते हुए या इरादा रखते हुए जिस दूसरे पक्ष से वादा किया गया है, उस पर अमल किया जाएगा और वास्तव में दूसरे पक्ष ने उस पर अमल किया है, वादा करने वाले पक्ष पर यह वादा बाध्यकारी होगा और वह इससे पीछे हटने का हकदार नहीं होगा, यदि पार्टियों के बीच हुए लेन-देन को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा करने की अनुमति देना असमान होगा, और यह इस बात पर ध्यान दिए बिना होगा कि पार्टियों के बीच पहले से कोई संबंध है या नहीं। प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत को शब्द के सख्त अर्थ में एस्टॉपेल जैसी ही सीमा से बाधित करने की आवश्यकता नहीं है। यह न्याय करने के लिए अदालतों द्वारा विकसित एक न्यायसंगत सिद्धांत है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे बचाव के माध्यम से केवल एक सीमित आवेदन दिया जाना चाहिए। तर्क या सिद्धांत में ऐसा कोई कारण नहीं है कि इक्विटी को संतुष्ट करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो प्रॉमिसरी एस्टोपेल भी कार्रवाई के कारण के रूप में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। वचनबंधन के सिद्धांत की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि वादे पर निर्भरता में कार्य करने वाले वादे को कोई नुकसान उठाना पड़े। आवश्यक केवल इतना है कि वचन ने वचन पर निर्भरता में अपनी स्थिति बदल ली हो। वचन विबंध का सिद्धांत सरकार के विरुद्ध भी लागू किया गया है और कार्यकारी आवश्यकता पर आधारित रक्षा को स्पष्ट रूप से नकारात्मक कर दिया गया है। जहां सरकार यह जानते हुए या यह इरादा रखते हुए वादा करती है कि उस पर वादे के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और वास्तव में, वादे पर भरोसा करते हुए कार्य करते हुए, वह अपनी स्थिति बदल देती है, तो सरकार को वादे से बंधा हुआ माना जाएगा और वादा किया जाएगा। वादे के अनुसार सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय है, इसके बावजूद कि वादे पर कोई विचार नहीं किया गया है और वादे को औपचारिक अनुबंध के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, जैसा कि संविधान के **अनुच्छेद 299 द्वारा अपेक्षित है।** . . . . . यदि सरकार द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि बाद में सामने आए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को उसके द्वारा किए गए वादे पर रोक लगाना असमान होगा, तो अदालत वादे के पक्ष में इक्विटी नहीं उठाएगी और उसे लागू नहीं करेगी। सरकार के खिलाफ

वादाखिलाफी. ऐसे मामले में वचनबंधन का सिद्धांत विस्थापित हो जाएगा क्योंकि तथ्यों पर, समानता के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि सरकार को उसके द्वारा किए गए वादे से बाध्य रखा जाए। यदि सरकार दायित्व का विरोध करना चाहती है, तो उसे अदालत को यह बताना होगा कि बाद की कौन सी घटनाएँ हैं जिनके कारण सरकार दायित्व से मुक्त होने का दावा करती है और यह अदालत को तय करना होगा कि क्या वे घटनाएँ ऐसी हैं सरकार के विरुद्ध दायित्व को लागू करने को असमान बनाना। विधायी शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध कोई वचनबद्ध रोक भी नहीं हो सकती है। विधानमंडल को वचनबंधन के सिद्धांत का सहारा लेकर अपने विधायी कार्य करने से कभी भी रोका नहीं जा सकता है। " जब उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, तो उत्तरदाताओं के पास प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के नियम की प्रयोज्यता से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उत्तरदाताओं ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी है कि यह इतना असमान था कि सरकार को वचनबंधन के तहत दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए था। उत्तरदाताओं के लिए यह आवश्यक था कि वे इन रिट याचिकाओं के रिकॉर्ड पर यह पुष्टि करने के लिए सामग्री रखें कि कर रियायत को रुपये के कारोबार की सीमा तक कम किया जाना चाहिए। एक साल में 5,00,000.

9. मोतीलाल पदमपत चीनी मिल मामले का अनुपात [1979] 44 STC 42 (SC); AIR 1979 SC 621, सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा पूर्णामी ऑयल मिल्स में लागू किया गया था राज्य केरल **[1987] 65 एसटीसी 1**; एआईआर 1987 एससी 590। उस मामले में भी खरीद कर से संबंधित छूट को 5 साल की अवधि के लिए एक अधिसूचना द्वारा अनुमति दी गई थी और बाद की अधिसूचना के माध्यम से, दी गई रियायत में कमी की गई थी। इन तथ्यों पर, उनके आधिपत्य ने प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत को लागू करते हुए निर्देश दिया कि छूट पूरी अवधि तक जारी रहेगी, जैसा कि पिछली अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

10. भारत जनरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड v में। राज्य महाराष्ट्र [1989] 72 STC 354 (SC); जेटी (1988) 4 एससी 204 तथ्य अलग थे। छूट अधिसूचना **बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1959 की धारा 41 के तहत जारी की गई थी।** हालांकि, विधानमंडल ने अधिनियम में संशोधन किया और धारा 41ए पेश की। चूंकि यह प्रावधान विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था, इसलिए वचनबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा और कानून की स्थिति मोतीलाल पदमपत चीनी मिल्स के मामले में उनके आधिपत्य द्वारा स्पष्ट की गई थी; केस [1979] 44 STC 42 (SC); AIR 1979 SC 621, जिसके प्रासंगिक उद्धरण हम पहले ही उद्धृत कर चुके हैं।

11. श्री बकुल ऑयल इंडस्ट्रीज v में। राज्य गुजरात [1987] 64 STC304 (एससी); AIR 1987 SC 142, उनके आधिपत्य ने कोई अलग सिद्धांत नहीं रखा। उनके आधिपत्य ने माना कि सरकार द्वारा दी गई छूट केवल रियायत के माध्यम से थी और राज्य सरकार के पास रियायत वापस लेने या रद्द करने की शक्ति थी। उनके आधिपत्य ने आगे स्पष्ट किया कि निरस्तीकरण या

वापसी की यह शक्ति एक सीमा के अधीन होगी, अर्थात। , वचनबंधन के नियम के उल्लंघन में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सरकार अपने द्वारा पहले दी गई छूट को तभी वापस ले सकती थी, जब ऐसा प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के नियम का उल्लंघन किए बिना और उद्योगों को उक्त कर के भुगतान से छूट का दावा करने से वंचित किए बिना किया जा सकता था। बिंद्रा की क़ानून की व्याख्या में (7वाँ संस्करण, अध्याय XXIX, पृष्ठ 810 पर) "मंत्रियों पर समिति" पावर रिपोर्ट, संसद द्वारा अधीनस्थ शक्ति के रूप में सौंपी गई शक्तियों की सराहना करते हुए, इस प्रकार दर्ज की गई है: " कानून बनाने की शक्ति, जब संसद द्वारा प्रत्यायोजित की जाती है, संसद की अपनी कानून बनाने की शक्ति से भिन्न होती है। संसद सर्वोच्च है और कानून बनाने की उसकी शक्ति असीमित है। यह महानतम कार्य कर सकता है; यह सबसे छोटा कार्य कर सकता है। यह विशाल साम्राज्य के लिए सामान्य कानून बना सकता है, यह किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में उनमें से कोई विशेष अपवाद बना सकता है। यह प्रदान कर सकता है - और वास्तव में प्रदान किया गया है - वृद्धावस्था के भुगतान के लिए वैधानिक शर्तों को पूरा करने वाले सभी लोगों को पेंशन दी जाती है; यह रोचेस्टर्न के बिशप के रसोइये को जलाकर मार डालने का प्रावधान भी कर सकता है - और वास्तव में प्रदान भी किया है। लेकिन संसद द्वारा सौंपी गई कोई भी शक्ति आवश्यक रूप से एक अधीनस्थ शक्ति है, क्योंकि यह उस अधिनियम की शर्तों द्वारा सीमित है जिसके तहत इसे सौंपा गया है। " दिल्ली कानून अधिनियम के संदर्भ में, **1912 [1951] एससीआर 747 (पेज 997 पर)**), मुखर्जी, जे., ने देखा कि विधायिका द्वारा जो सौंपा जा सकता है वह अधीनस्थ कानून का कार्य है जो अपने स्वभाव से उस क़ानून का सहायक है जो इसे बनाने की शक्ति सौंपता है। प्रतिनिधिमंडल की वैधता पूरी तरह से एक सहायक उपाय के रूप में इसके उपयोग पर निर्भर करती है जिसे विधानमंडल अपनी विधायी शक्ति का प्रभावी और पूर्ण रूप से प्रयोग करने की शक्ति के लिए आवश्यक मानता है। क्रेज़ ऑन "क़ानून क़ानून", साठ संस्करण (1963) एसजीजी एडगर द्वारा (पृष्ठ 297) ने अधीनस्थ विधान और क़ानून क़ानून के बीच अंतर दर्शाया: " अधीनस्थ कानून (इस अध्याय में वर्णित प्रकार) और क़ानून कानून के बीच प्रारंभिक अंतर इस तथ्य में निहित है कि एक अधीनस्थ कानून बनाने वाला निकाय अपने प्रत्यायोजित या व्युत्पन्न प्राधिकरण की शर्तों से बंधा होता है, और कानून की अदालतें, एक सामान्य नियम के रूप में , इस प्रकार बनाए गए नियमों आदि को तब तक प्रभावी नहीं करेगा, जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि नियमों की वैधता से पहले की सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं। क़ानूनों की वैधता को अदालतों द्वारा प्रचारित नहीं किया जा सकता है, एक सामान्य नियम के रूप में प्रत्यायोजित कानून की वैधता को प्रचारित किया जा सकता है। इसलिए अदालतों को (1) उचित प्रमाण की आवश्यकता होगी कि नियम वैधानिक प्राधिकरण के अनुसार बनाए और प्रख्यापित किए गए हैं, जब तक कि क़ानून उन्हें न्यायिक रूप से

ध्यान देने का निर्देश नहीं देता है; (2) इसके विपरीत स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के अभाव में, यह पूछताछ कर सकता है कि क्या नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग उस क़ानून के प्रावधानों के अनुसार किया गया है जिसके द्वारा इसे बनाया गया है, या तो अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में, प्रपत्र या विनियम का सार, या विनियम से जुड़ी मंजूरी, यदि कोई हो; और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत वैधानिक अनिवार्यताओं का पालन करने में विफल रहने वाले विनियमन को अमान्य और अधिकारेतर के रूप में खारिज कर सकती है। " इस प्रकार, कानून ने विधानमंडल की शक्तियों और उस प्राधिकरण के बीच अंतर किया जो केवल कानून की प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रतिनिधि विधानमंडल के समान संप्रभु अधिकार का दावा नहीं कर सकता। विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा का तर्क, कि आक्षेपित अधिसूचना, अनुलग्नक P1, एक क़ानून के बराबर एक विधायी अधिनियम के बराबर है जब इसकी जांच की जाती है उपरोक्त चर्चा के आलोक को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा के राज्यपाल ने अधिसूचनाएं, अनुलग्नक P1 और P2 जारी करते समय, अधिनियम की धारा 13 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य किया था और यह केवल यह एक अधीनस्थ विधान है और इसकी तुलना विधायिका द्वारा बनाए गए क़ानून से नहीं की जा सकती। इस प्रकार, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि सतगुर ऑयल मिल्स मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय; केस **[1989] 73 STC 341 (P और H)**; **ILR (1989) 1 पी और एच 175**, कुछ दिन बाद सही कानून और अधिसूचना, अनुलग्नक के माध्यम से छोटे उद्योगों को अधिनियम के तहत कर में छूट की अनुमति दी गई पी2, आक्षेपित अधिसूचना, अनुलग्नक पी1, और के माध्यम से वापस नहीं लिया जा सकाहरियाणा सरकार को प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के नियम द्वारा छोटी औद्योगिक इकाइयों को दी गई रियायत वापस लेने से रोक दिया गया था। खादी और ग्रामोद्योग का मामला एक अलग पायदान पर खड़ा है। वचन-बंधन का नियम उन मामलों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यह उन्हें दी गई एक रियायत थी और इसे राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता था। खादी उद्योग से संबंधित मामलों में लागू अधिसूचना अनुबंध पी1 कानूनी है और हरियाणा के राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत है। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम अधिसूचना, अनुलग्नक पी1, दिनांक 30 दिसंबर, 1987 को रद्द करते हैं; लघु उद्योगों से संबंधित रिट याचिकाओं की अनुमति दें, i. इ , सी. डब्ल्यू. पी.एस. संख्या 757, **1026, 1120, 1123, 1244, 1338, 1396, 1553, 2204, 2292, 2794, 2795, 3573, 3574, 4753, 5513, 6802, 7265, 7524 1988 और 1989 का सी.डब्ल्यू.पी. नं. 2708**और सी.डब्ल्यू.पी.एस. को बर्खास्त करें। संख्या 3449, 3480, 3580, 3631, 3644, 3681, 3756, 3921, 3924, 3925, 4146, 4213, **4375, 4987, 5216, 5285, 10125, 10335 में से 19 88 और सी.डब्ल्यू.पी. 1989 का क्रमांक 1784**खादी उद्योग से संबंधित।

कोई लागत नहीं.

*अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के : सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
जिला न्यायालय, गुरुग्राम, हरियाणा